



2026:AHC:66290

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 7559 वर्ष 2026

ए. के राणा आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: बुद्धि सागर त्रिपाठी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 64

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा

1. श्री एस.के. उपाध्याय, अधिवक्ता श्री बुद्धि सागर त्रिपाठी, आवेदक के अधिवक्ता, श्री एन.के. शर्मा, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन केस अपराध संख्या-62 वर्ष 2025 में धारा 318(2), 318(4), 61(2)(बी), 111(2)(बी), 341(1) बी.एन.एस., और 66डी ऑफ आई.टी. एक्ट, थाना-कोतवाली, जिला- आगरा के तहत ज़मानत पर आवेदक को ज़मानत पर बढ़ाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। जांच के दौरान आवेदक का नाम सामने आया। आवेदक मेसर्स मीनाक्षी फार्मा का मालिक है। उक्त फर्म के पास अनुसूची-X में निर्दिष्ट दवाओं को छोड़कर अनुसूची C और C(1) में निर्दिष्ट थोक दवाओं द्वारा बिक्री या बिक्री के लिए स्टॉक बेचने या प्रदर्शन (या प्रस्ताव) करने का लाइसेंस था। आवेदक की फर्म ने सह-आरोपी मुकेश बंसल, सह-आरोपी सोहित बंसल और सह-आरोपी संजय बंसल की फर्म को उपरोक्त दवाओं की आपूर्ति की। कथित दवाओं का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया गया था। सभी दवाएं ई-वे बिल और जीएस.टी. चालान के माध्यम से बेची गई थीं। इसके अलावा, आवेदक आपूर्ति की गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दवाओं का निर्माता नहीं है। इस स्तर पर, यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि कथित दवाएं नकली या घटिया गुणवत्ता वाली थीं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। आवेदक न तो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है और न ही उसने ऐसे सिंडिकेट की ओर से काम किया है। इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि सह-आरोपी मुकेश बंसल, सोहित बंसल और संजय बंसल को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-36251 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 17.10.2025 के आदेश के माध्यम से ज़मानत दे दी गई है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को पूरक हलफनामे के प्रस्तर-3 में समझाया गया है। आवेदक 17.12.2025 से जेल में है। यदि उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन अभिलेखों से उपरोक्त प्रस्तुतियों पर संतोषजनक ढंग से विवाद नहीं कर सका।

5. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। जांच के दौरान आवेदक का नाम सामने आया। इस स्तर पर, यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि कथित दवाएं नकली या घटिया गुणवत्ता वाली थीं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। सह-आरोपी मुकेश बंसल, सोहित बंसल और संजय बंसल को इस अदालत ने ज़मानत दे दी है। इसके अलावा, आवेदक वर्तमान में तीन महीने से अधिक समय तक कैद है और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर जब राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि ज़मानत पर बढ़ाया जाता है, तो मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, या तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाह को डराएगा, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा किये जाने का हकदार है।

6. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक, ए.के. राणा को निम्नलिखित शर्तों पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए:

i. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;

iii. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

एसएस

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

Translated Version. Not for Legal Use.